

कारीगर नज़रिया

● यह कारीगर समाज का ज्ञान आंदोलन है। ●

● कारीगर समाज अपने नज़रिये पर फक्र करें। उसका नज़रिया, उसकी विद्या उसका हुनर पढ़े-लिखे लोगों के मुकाबले कम दर्जे का नहीं है। ●

● कारीगर नज़रिये पर गढ़ी गई दुनिया आज की दुनिया से एक बेहतर, खुशहाल और बराबरी की दुनिया बनेगी। ●

अंक 2

जुलाई 2011

सहयोग राशि : 2 रुपये

कारीगर अपनी विद्या पर फक्र करें

1. 'कारीगर नज़रिया' कारीगर समाज का ज्ञान आंदोलन है।
2. कारीगर अपने ज्ञान, हुनर और मेहनत के जरिये काम करता है।
3. कारीगर को मजदूर समझना बंद होना चाहिए। उनका वाजिब हक उन्हें मिलना चाहिए।
4. कारीगर सरकार की गलत नीतियों के शिकार हैं। उनकी मेहनत का पूरा दाम नहीं मिलता। उनके हुनर का भी पूरा दाम नहीं मिलता। उनके ज्ञान का दाम मिलना तो दूर, उसे पहचाना भी नहीं जाता।
5. कारीगर का अपना नज़रिया होता है। यह इंसानियत का नज़रिया है, कुदरती नज़रिया है। कम्पनियों के शोषण और धुएं से निजात का रास्ता कारीगर के पास है।
6. नीतियाँ, योजनायें और कार्यक्रम बनाने में कारीगर की राय शामिल हो तो खुशहाली का माहौल बन सकता है।
7. कारीगर नज़रिये को इज्जत होगी तभी उसकी आमदनी दूसरों के बराबर होगी और तभी ये दुनिया बचेगी।
8. कारीगर अपने नज़रिये पर फक्र करें और अपना ज्ञान आंदोलन खड़ा करें।

लोकविद्या मंच

लोकविद्याधर समाज की एकता का मंच

जो लोग स्कूल-कॉलेज नहीं गए हैं उन्हें लोकविद्याधर

बुनकरों का बिजली बकाया माफ हो

वाराणसी, 14 जून बुनकर बिरादराना तंजीम चौदहो की एक पंचायत मोहल्ला कटेहर में चौदहो तंजीम के सरदार जनाब मकबूल हसन अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बनारस के बुनकरों पर बिजली बकाया के संबंध में खुले मंच पर चर्चा हुई।

बुनकर वेलफेयर संघर्ष समिति के संयोजक हाजी रहमतुल्लाह अंसारी ने सुझाव के दौरान बनारस के कमजोर वर्ग के बुनकरों पर चर्चा करते हुए कहा कि बनारस के बुनकर, जो कारीगर व मजदूर हैं, उनके समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बुनकरों का तेजी के साथ पलायन, आत्महत्या, बुनकर द्वारा खून बेचना बनारस की एकता पर दाग है। जो पूरी दुनिया को रोशनी देता था आज वही बुनकर रोजी-रोटी के अलावा रोशनी का मोहताज हो गया है। अब समय आ गया है, बुनकरों को जागना होगा और संघर्ष करने की जरूरत है। किसान नेता लक्ष्मण प्रसाद मौर्य ने 'कारीगर नज़रिया' पर चर्चा करते हुए कहा कि किसान और बुनकर भाई-भाई हैं। एक रोटी देता है तो दूसरा कपड़ा। बुनकरों की हर लड़ाई को हम किसान अपनी लड़ाई समझकर लड़ेंगे। मुर्ी बंद का समर्थन करते हुए लोकविद्या मंच के संयोजक दिलीप 'दिली' ने कहा कि कारीगर अपने काम का नुकसान तभी करे जब सरकार के कामों में रुकावट डालने की क्षमता रखता हो, तभी हमारा मकसद कामयाब हो

क्योंकि राजनैतिक दलों ने हमें केवल वोट का हिस्सा बना रखा है। अपने अधिकार को पाने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। विद्या आश्रम के किसान नेता श्री सुनील सहस्रबुद्धे ने कहा कि बुनकरों को निजाम बदलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। घर बैठकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी ताकत को पहचानें। जिस दिन किसान-बुनकर एक हो जाएंगे हिन्दुस्तान का निजाम बदल जाएगा। उन्होंने बुनकरों तथा बुनकर सरदार साहेबान को विश्वास दिलाया कि हमारी यूनियन बुनकरों की हर लड़ाई में साथ-साथ रहकर लड़ाई लड़ेगी। सरदार जहीरुद्दीन अंसारी ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की गूंगी-बहरी सरकार को बुनकर समाज अब उनकी ही भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। अफजाल अंसारी ने कहा कि बुनकरों की लड़ाई तंजीमी सतह पर जरूरी है। हमें अपनी लड़ाई अपने बल पर लड़ने की जरूरत है। राजनीतिक दलों को इस लड़ाई से दूर रखना होगा। अंत में सरदार मकबूल हसन अंसारी ने लोगों की चर्चा के बाद कहा कि मुर्ी बंद कर आंदोलन होगा। बुनकरों की बिजली माफी की लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। इस संबंध में बनारस के सभी तंजीमो के सरदार साहेबान से दिनांक 15.6.2011 को विचार करके आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में सर्वश्री अतीक अंसारी, जुनैद अहमद, एहसान अली, मो. चाचा, मो. अहमद, पार्षद अनीसुरहमान, नेगन्तवीर मो. तशीम शक्ति ने अपने अपने विचार रखे।

लोकविद्या मंच

लोकविद्याधर समाज की एकता का मंच

जो लोग स्कूल-कॉलेज नहीं गए हैं उन्हें लोकविद्याधर कहते हैं। वे लोकविद्या के बल पर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। किसान, कारीगर, छोटे दुकानदार, आदिवासी और इनके परिवार लोकविद्याधर हैं। लोकविद्याधर समाज के इन घटकों को बाजार में उनके श्रम और ज्ञान का मूल्य नहीं मिलता, राष्ट्रीय संसाधनों जैसे बिजली का वाजिब हिस्सा नहीं मिलता, इन्हें इनके रोजगारों से बड़े पैमाने पर बेदखल किया जा रहा है और आधुनिक शिक्षा में इनके प्रवेश को परोक्ष रूप से रोक दिया गया है।

लोकविद्या मंच लोकविद्याधर समाज की एकता को आकार देने का मंच है। लोकविद्या के धनी इन समाजों को सबसे ज्ञानी समाज होने का दावा यह लोकविद्या मंच करता है। लोकविद्या मंच बाजार, राष्ट्रीय संसाधन, शिक्षा और बेदखली के मुद्दों पर लोकविद्याधर समाज का अपना एक नजरिया सामने लाने का मंच है। इन क्षेत्रों में लोकविद्याधर समाज को बराबरी की हैसियत मिले और पूरे समाज का हित हो, लोकविद्या मंच का यही प्रयास है। —दिलीप कुमार 'दिली' संयोजक, लोकविद्या मंच

पाषाण नक्कासी कला के कारीगर

रामनगर में मछरहट्टा और साहित्यनाका क्षेत्र में पत्थर पर नक्कासी का कार्य करने वाले बचाऊ श्रीवास्तव, द्वारिका प्रसाद, जोखनजी और बच्चेलालजी से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस समय यहां 500 से 600 कारीगर हैं। आठ घण्टे काम करके 150 से 200 रुपये तक कमा लेते हैं। पहले हाथ से काम करते थे अब बिजली का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो नियम से नहीं मिलती है। तैयार माल व्यापारियों के माध्यम से देश-प्रदेश में जाता है। इन लोगों का कहना है कि मुनाफे का बड़ा हिस्सा व्यापारी खाता है। समूह में ही अपना-अपना पत्थर झांसी से मंगाते हैं। इन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। इनके श्रम और हुनर की कोई कीमत ही नहीं है। समझिए कि मजदूरी और वह भी कम में ही काम करते हैं। इनका कोई संगठन नहीं है। ये संगठन से जुड़ना चाहते हैं। 'कारिगर नजरिया' के मार्फत अपनी बात समाज में रखना चाहते हैं।

—ललित नारायण

रुड़त के कारिगर लड़कों को नुकसान पहुंचाएंगे। लोकविद्या मंच के संयोजक दिलीप 'दिली' ने कहा कि कारीगर अपने काम का नुकसान तभी करे जब सरकार के कामों में रुकावट डालने की क्षमता रखता हो, तभी हमारा मकसद कामयाब हो पाएगा। बुनकर फाउण्डेशन के अध्यक्ष अनवरुल हक अंसारी ने कहा कि मुर्ी बंद कर तंजीमी सतह पर लड़ाई होनी चाहिए

दिनांक 15.6.2011 का विचार करके आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में सर्वश्री अतीक अंसारी, जुनैद अहमद, एहसान अली, मो. चाचा, मो. अहमद, पार्षद अनीसुरहमान, रेयाजुद्दीन, मो. वशीम आदि ने अपने-अपने विचार रखे।

—हाजी रहमतुल्लाह अंसारी,
संयोजक, बुनकर वेलफेयर संघर्ष समिति

बेरोजगार हो जाएंगे 22 लाख मछुआरे

बिहार के कुल 28 हजार सरकारी जलाशयों में से 26 हजार जलाशय ओपेन डाक के माध्यम से गैर-मछुआरों के हाथों में चले जाएंगे। राष्ट्रीय सहारा अखबार में 21 जून को छपी खबर के अनुसार समय रहते सहकारिता विभाग वे समितियां निर्बंधित करने का दायित्व पूरा नहीं कर सका जिसका खामियाजा मछुआरा समाज को भुगतना पड़ेगा। सूबे के कुल 28 हजार सरकारी जलाशयों में से 26 हजार जलाशय ओपेन डाक के माध्यम से गैर मछुआरों के हाथों में चले जाएंगे।

जलाशयों की बंदोबस्ती मामले में सहकारिता विभाग और मत्स्य विभाग के बीच उत्पन्न तकनीकी पेंच में सूबे के मछुआरे एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं। सहकारिता विभाग द्वारा जो रवैया अपनाया गया है उसके चलते सूबे के बाईस लाख मछुआरे अगले सात वर्षों के लिए बेरोजगार हो जाएंगे। उन्हें सरकारी जलाशयों से हाथ धोना पड़ जाएगा और उनके सामने बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मछुआरे पलायन को मजबूर हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि सूबे के 534

प्रखंडों में से मात्र 150 प्रखंडों में ही समय रहते मछुआरा समिति का गठन हो सका है। बाकी 384 प्रखंडों के जलाशयों को खुले डाक के माध्यम से बंदोबस्त किया जाएगा। बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार सरकार ने मछुआरा समिति गठित करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की थी। समिति गठित करने के लिए 30 अप्रैल तक जिला मत्स्य पदाधिकारी और 31 मई तक जिला पदाधिकारी के यहां आवेदन जमा करना था। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त हो जाने के बावजूद सूबे के सभी प्रखंडों में समिति का गठन नहीं हो सका जिसका खामियाजा सीधे तौर पर सूबे के मछुआरों को भुगतना पड़ेगा। अररिया जिले के फारबिसगंज, नरपतगंज, जोकीहाट, कुर्साकांटा व पलासी सहित पांच प्रखंडों व मोतिहारी जिले में ओपेन डाक के माध्यम से जलाशयों की बंदोबस्ती शुरू कर दी गई है। इसके चलते मछुआरों के सामने भारी परेशानी उत्पन्न हो गई है।

(राष्ट्रीय सहारा, 21/6 से साभार)

कविता

लेबे जमीनियां

लेबे जमीनियां धुर धुर

अइसे न देखा घूर घूर

अब न सहल जाई मार अउर गारी

अब न बेकार में देखा बरियारी

हरवा से देबे अब धुर

अइसे न देखा घूर घूर

चले नहीं देब अब कवनी चलाकीं

उहई तीहें चाही जवन बाय अब बाकी

बहुत झीकला अखियां में धुर

अइसे न देखा घूर घूर

चुप नहीं बैठब पाई-पाई के हिसाब हीई

तीहरे फरेबवा क मौटकी किताब हीई

सुदवा के साथे लेबे मूर

अइसे न देखा घूर घूर

कयदा कानून लील गईला सरकार के

हमरा के रखला हमेशा दुतकार के

तीरी देब तीहरी गरूर

अइसे न देखा घूर घूर

—विजय विनीत

(द संडे इंडियन से साभार)

कारिगरों के बीच 'कारिगर नजरिया'

कारिगरों के बीच 'कारिगर नजरिया' की ओर से वार्ताओं का दौर चला है। बनारस शहर की दौलत बनारस के कारिगरों द्वारा पैदा की जाती है। साड़ी के बुनकर, पत्थर और लकड़ी के नक्काशी के कारिगर, पंखे और मोटर पम्प के कारिगर, पान के कारिगर, मिठाई बनाने वाले कारिगर, रंगरेज, अचार और पापड़ के कारिगर, लोहे और लकड़ी के मिस्त्री, पानी पर जीने वाले मछुआरे, नाई व धोबी समाज के कारिगर और न जाने कितने काम करने वाले हुनरमंद कारिगर! यह सूची लम्बी है। जो मजदूर हैं वे भी कारिगर ही हैं, लेकिन उनके काम छीन जाने के चलते मजदूरी करने के लिए मजबूर बने हैं।

'कारिगर नजरिया' की ओर से लोहता, रामनगर, बहादुरपुर, भोजपुर चौरहट, आलमपुरा, पीलीकोठी में कारिगरों के बीच बैठकें की गईं। इन क्षेत्रों में ज्यादातर बुनकर ही रहते हैं। लेकिन कोशिश यह रही कि सभी किस्म के कारिगर एक मंच पर आकर अपनी बात रखें। बजरडीहा, लल्लापुरा, पुरानापुल, कज्जाकपुरा, शिवाला, सरैया, ताजीपुरा, दोषीपुरा, दशाश्रमध घाट आदि स्थानों पर रहने वाले विभिन्न कारिगरों के बीच वार्ताएं हुईं। इन बैठकों और वार्ताओं का उद्देश्य यह था कि लगभग सभी तरह के कामों के कारिगरों की समस्याएं एक जैसी हैं, इस बात को उजागर करना। सभी किस्म के कारिगरों को आपस में एका बनाए बिना उनकी हालत में बदलाव ला पाना सम्भव नहीं है।

पीलीकोठी के नजीर और इकबाल तथा काष्ठ खिलौना के रमाशंकर के अनुसार राजनैतिक नेताओं से उम्मीद नहीं की जा सकती। वे केवल अपने बारे में सोचते हैं। रामनगर के बच्चालाल व तूफानी सोनकर कारिगर के हुनर की ताकत को बेमिसाल मानते हैं लेकिन उनके शोषण को रोकने का कारगर रास्ता न होने से बेचैन हैं। लोहता के मोहम्मद इस्माइल, गुलाम रसूल कहते हैं कि बुनकर को न दाम मिलता है, न बिजली, न शिक्षा न अस्पताल। कौन है हमारा? नाई समाज और पटरी पर धंधा करने वाले प्रशासन द्वारा रोज-रोज भगाए जाने से परेशान हैं। भोजपुर के जमालुद्दीन और सरदार मुईनुद्दीन के अनुसार कारिगर को अपने काम का दाम नहीं मिल रहा तो

बुनकर दावा पेश करें

आलमपुरा के सरदार आसिफ जमाल से वार्ता

आलमपुरा क्षेत्र में बुनकरों की हालत जानने के उद्देश्य से 'कारिगर नजरिया' की टीम पहुंची। तंजीम पांचों के सरदार आसिफ जमाल से बातचीत शुरू हुई। उसी समय वहां कई बुनकर भी आ गए। तंजीम पांचो छिन्नपुरा के सरदार मुहम्मद मुर्तुजा, बुनकर बिरादराना से सरदार मु0 अहमद, मु0 मुस्तफा, मकबूल हसन और मु0 हारून भी उपस्थित थे। बातचीत के दौरान बुनकर समाज की कई समस्याएं उजागर हुईं, जो नीचे दी जा रही हैं। वार्ता में कुछ सुझाव भी उभर कर आए।

1. सरकार की मदद सोसाइटी के माध्यम से नहीं सीधे बुनकर को मिलनी चाहिए।
2. बुनकर को उसका बाजार वापस मिलना चाहिए।
3. बुनकर की मजदूरी पिछले आठ-दस साल में नहीं बढ़ी है, छठें वेतन आयोग के आधार पर और बढ़ती महंगाई के हिसाब से उसे बढ़ा दिया जाना चाहिए।

4. बुनकरों का बिजली बिल बकाया माफ हो।

'कारिगर नजरिया' की ओर से यह बात सामने आई कि कारिगर को अपने ज्ञान के मूल्य का दावा करना चाहिए। यह व्यवस्था और सरकार की नीति कारिगर के श्रम का पूरा मूल्य ही नहीं देती और ज्ञान के मूल्य को तो डकार जाती है। बुनकर समाज इस बात पर सोचना शुरू करें।

बुनकर समाज में इतनी ताकत है कि वह देश की जनता को कपड़ा मुहैया करा सकता है। बुनकर समाज को यह दावा पेश करना होगा कि कपड़ा उद्योग की नीति बनाने में बुनकर समाज अगुवा हो। बुनकर समाज के सरदार और बुनकरों को मिलकर ये दावा पेश करना होगा। 'कारिगर नजरिया' की ओर से एहसान अली, दिलीप कुमार 'दिली' एवं लक्ष्मण प्रसाद वार्ता में शामिल हुए।

इलेक्ट्रॉनिक मोटर पंप और पंखे के कारिगर

-ललित नारायण

वाराणसी के आसपास तरह-तरह की कारिगरी का कार्य होता रहा है। उनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक (विद्युत चलित) पंप और पंखा बनाने वाले कारिगर हैं। इनकी शुरुआत सिन्धी पंखा उद्योग से शुरू हुई। करीब 20-25 साल पहले सिन्धी पंखे में कार्य करने वाले कारिगर कम वेतन की वजह से अलग हो गए और अपनी कारिगरी का स्वयं प्रयोग शुरू किए। उन कारिगरों ने गांव के नौजवानों को सिखाने के साथ ही काम को आगे बढ़ाने का प्रयास शुरू किया और आज इस व्यवसाय पर पूरी तरह से स्थानीय कारिगर स्थापित हो गए। कंपनी के पंखे से सस्ता और टिकाऊ पंखा और पंप देश को मुहैया करा रहे हैं। कंपनी का जो सामान 2000 रुपये में मिलता है, उसको यहां के कारिगर 1000 रुपये में तैयार करके देते हैं। लेकिन पूंजी परस्त सरकारों की नीति ने आज तक इनके कारिगरी, ज्ञान, कौशल को बढ़ावा न देकर तरह-तरह के हथकंडों से इनको व इनकी कारिगरी को दबाने की कोशिश की। लेकिन ये कारिगर अपने संघर्ष को जारी

भरने का कार्य) मुख्य है। मुख्य रूप से लोहा, पीतल, एल्युमिनियम, तांबा आदि धातुएं और टिन का प्रयोग होता है। धातुओं की बढ़ती कीमत ने इन कारिगरों के धंधे पर गहरा संकट खड़ा कर दिया है। इनके कारिगर ज्यादातर स्कूल नहीं गए हैं। इनमें कोई 5 तक या 10वीं पास है, लेकिन ये अपनी कला से आधुनिक इंजिनियरिंग को सीधी टक्कर दे रहे हैं। इनकी अपनी कारिगरी है, इनको किसी प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं है। इनका प्रमाण-पत्र इनकी कला का आविष्कार है।

इस व्यवसाय के कुछ कुशल कारिगर भरत प्रसाद मौर्य, बलराम पटेल, खन्ना जी रुपनपुर नटुई के निवासी हैं। ये बताते हैं कि इस व्यवसाय में करीब 10 हजार लोग जुड़े हैं। हम अपना माल कलकत्ता, मद्रास, मुम्बई, दिल्ली आदि अन्य राज्यों में बेचते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां पेटेंट का धौंस देकर हमारे माल को लुटवाती रहती हैं। इन लूटने वालों में सेल टैक्स विभाग, पुलिस विभाग, खनिज विभाग प्रमुख रूप से हैं। हमारी कोई

पर धंधा करने वाले प्रशासन द्वारा रोज-रोज भगाए जाने से परेशान हैं। भोजपुर के जमालुद्दीन और सरदार मुईनुद्दीन के अनुसार कारीगर को अपने काम का दाम नहीं मिल रहा तो आलमपुरा के हाजी नुरुद्दीन व हमीदुर्रहमान बिजली के न मिलने व सोसायटियों के मार्फत बुनकरों को राहत दिलाने वाली व्यवस्था से नाराज हैं। रजक समाज और मछुआरा समाज घाट की व्यवस्था-कानून से नाराज हैं। कारीगर समाज का शोषण कर, उसे नाराज रखकर बनारस की दौलत का क्या मतलब रह गया है?

‘कारिगर नजरिया’ की इन वार्ताओं से यह उभरकर आया कि सभी किस्म के कारिगरों को मुख्य रूप से चार चीजें परेशान कर रही हैं—बाजार, जिसमें वे अपने श्रम और ज्ञान का मूल्य नहीं कमा पाते, राष्ट्रीय संसाधन (बिजली) का उन्हें बराबर हिस्सा नहीं मिलता, शिक्षा के दरवाजे बंद हैं और हर कारिगरी में बेदखली की तलवार उनपर लगातार टंगी रहती है। कारिगर समाज को इन चारों समस्याओं का हल खोजना होगा। अपने-अपने समाजों, काम की जगहों, परिवार और मनोरंजन के स्थानों पर इन विषयों को चर्चा का मुद्दा बनाना होगा।

किसान, कारिगर, आदिवासी, छोटा दुकानदार एक हों

क्योंकि

सूचना युग में कम्प्यूटर-इंटरनेट और वैश्रीकरण मिलकर किसान, कारिगरी, छोटी दुकानदारी को उजाड़ रहे हैं, मजदूरी को घटा रहे हैं।

कैसे?

1. इनके श्रम को बाजार में कम दाम देकर
2. इनके ज्ञान यानि लोकविद्या को लूटकर
3. शिक्षा को महंगी बना कर व इन्हें नये ज्ञान से वंचित कर

आइए

1. लोकविद्या के बल पर जीविका के अधिकार का दावा करें।
2. सूचना युग में श्रम और ज्ञान की लूट को रोकने के उपाय खोजें।
3. बाजार और ज्ञान के क्षेत्र में हो रहे शोषण की समझ और विरोध को आकार दें।

की नीति ने आज तक इनके कारिगरी, ज्ञान, कौशल को बढ़ावा न देकर तरह-तरह के हथकंडों से इनको व इनकी कारिगरी को दबाने की कोशिश की। लेकिन ये कारिगर अपने संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। अगर इनको प्रोत्साहन मिला होता तो ये अपनी कारिगरी से पूरे देश को यंत्र मुहैया कराते। इस निर्माण में मुख्य रूप से मोल्डिंग (ढलाई), टर्निंग (मशीन द्वारा कटाई), बाइंडिंग (वायर

बाजार पूंजीवादी और उद्योग पुश्तैनी?

अमनउल्लापुरा (हड़शतल्ले) के मकबूल हसन अशफ़ी से वार्ता

‘कारिगर नजरिया’ को अशफ़ी साहब ने बताया कि गद्दीदार कारिगर को लड़ाकर तोड़ने का काम करते हैं। कारिगर में माल रोकने की क्षमता नहीं है। बाजार पूंजीपतियों के कब्जे में है। जबकि बाजार खुला होना चाहिए।

बंडाल बनाने वाले कारिगर

विज्ञान चाहे कितनी भी उन्नति कर ले लेकिन कुछ समस्याओं का हल अब भी परंपरागत तकनीक में ही छिपा है। नदी में बंडाल निर्माण कला एक ऐसी ही पारंपरिक तकनीक है। बंडाल नदी के खास हिस्सों में जलस्तर बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। काशी में गंगा का जलस्तर कम होने के कारण इस बार भी बिहार के कारिगरों द्वारा गंगा में बंडाल लगाया गया है।

इस वर्ष बंडाल लगाने का कार्य कोलकाता से शुरू हुआ है। यह गंगा में इलाहाबाद तक लगाए जाएंगे। कोलकाता से सर्वे के लिए जलमार्ग से निकलने वाले जहाज को मार्ग देने की दृष्टि से बनाए जाने वाले इन बंडालों का लाभ क्षेत्रीय नाविकों को अधिक मिलता है। वाराणसी में सामने घाट में गंगा में पूरब से पश्चिम की ओर करीब 75 फुट लंबा बंडाल लगाया गया है। इससे होगा यह कि बंडाल लगाए जाने की जगह से लेकर रामनगर किले के बीच पूर्वी छोर पर गंगा में पर्याप्त जल होगा। इससे बड़ी नौकाओं के गंगा के भीतर उभरी रेत में फंसने का खतरा भी समाप्त हो जाएगा। बंडाल में बांस की चटाई को बांस के फ्रेम में बांधकर पानी में खड़ा किया जाता है। इसे बांधने का काम खासतौर पर बिहार के कारिगर करते हैं। आठ सदस्यीय दल के मुख्य कारिगर नितीश की अगुवाई में चहनिया, छत्तरपुर, रघुनाथपुर, गाजीपुर, टिकरी में बंडाल लगा चुके हैं। नितीश के मुताबिक, मई के पहले सप्ताह में उन्हें चुनार में बंडाल लगाने का काम पूरा कर लेना था। नितीश की कई पीढ़ियां बंडाल बनाने के काम में जुड़ी हुई हैं।

(हमारे कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त जानकारी और अमर उजाला की खबर से)

में बेचते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां पेटेंट का धौंस देकर हमारे माल को लुटवाती रहती हैं। इन लूटने वालों में सेल टैक्स विभाग, पुलिस विभाग, खनिज विभाग प्रमुख रूप से हैं। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार पूंजीपतियों के दबाव में आकर हमारी कला को मान्यता नहीं देना चाहती है। उल्टे हमको अवैध व्यवसायी घोषित करने पर तुली है।

सरकारी सहायता सोसाइटी या एनजीओ के मार्फत न बंटे समाज की खुली पंचायत लगाकर सरकारी सुविधाएं बुनकर के सामने उसके खाते पर मिले।

‘कारिगर नजरिया’ की टीम के बीच यह सवाल खड़ा हो गया कि वाराणसी का साड़ी उद्योग परम्परागत उद्योग कहा जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि इसका बाजार शुद्ध रूप से पूंजीवादी है। कच्चा माल और तैयार माल की खपत इन दोनों ही सिरों पर पूंजीवादी महंत बैठते हैं। परम्परागत उद्योग किससे पहचाना जाएगा—तकनीक से, डिजाईन से, प्रक्रिया, बाजार या संगठन से या इन सबसे? बाजार शुद्ध पूंजीवादी हो और अन्य कम-अधिक परम्परागत हो तो क्या फिर भी उद्योग परम्परागत/पुश्तैनी कहलाएगा? उद्योग को परम्परागत होने के लिए क्या बाजार का स्थानीय होना भी जरूरी नहीं है?

—एहसान अली और दिलीप कुमार ‘दिली’

अपील व सम्पर्क

‘कारिगर नजरिया’ कारिगर समाज का अखबार है। इसमें कारिगर अपनी समस्याओं, माँगों, क्षमताओं और समाज के बारे में अपने नजरिये को सामने लायें।

सम्पर्क पता— विद्या आश्रम, सा 10/82 ए, अशोक मार्ग, सारनाथ, वाराणसी-221007

सम्पर्क फोन—
दिलीप कुमार ‘दिली’ मो. 9452824380
एहसान अली मो. 9336016119

कारिगर नजरिया का यह अंक प्रेमलता सिंह, एहसान अली व दिलीप कुमार ‘दिली’ के सहयोग से बनाया गया है। ‘कारिगर नजरिया’ के अगले अंक को तैयार करने में कारिगर समाज के लोग आगे आयें।